शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 48 अंक-47 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 27-04 दिसम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

कांग्रेस की इस हार का हिमाचल पर भी असर पड़ेगा

- सरकार की कठिनाइयां बढ़ेगी
- सरकार को अपना ही भार उठा पाना कठिन होगा
- मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर लोस चुनावों से पहले फैसला आने की संभावना

शिमला/शैल। क्या तीन राज्यों में कांग्रेस की हार का असर हिमाचल पर भी पड़ेगा यह सवाल इसलिये प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योकि पिछले कुछ अरसे से प्रदेश भाजपा कर्ज के आंकड़ों को और गारंटीयां पूरी न कर पाने को लेकर सुक्खू सरकार पर हमलावर है। कर्ज के आंकड़ों पर जिस तरह की ब्यान बाजी सरकार की ओर से सामने आ रही है उसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन 2022-23 और 2023-24 के बजट दस्तावेजों की भी सही जानकारी सरकार के सामने नहीं रख रहा है। जो गारंटीयां चुनावों में दी थी उनको पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह सब आम आदमी के सामने है। कर्ज और गारंटीयों पर जो जनधारणा बनती जा रही है उससे स्पष्ट है कि यदि सरकार समय रहते न संभली तो लोकसभा में सुक्खू सरकार के लिये एक भी सीट जीत पाना संभव नहीं होगा। वैसे सुक्खू सरकार और प्रदेश भाजपा में बीते एक वर्ष में इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो सरकार से कोई नाराजगी हो सकती है लेकिन किसी भाजपाई को नहीं। क्योकि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कोई बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया ही नहीं गया। जब प्रशासन में काम करने वाले पुराने ही अधिकारी सुरक्षित रहे तो भाजपाइयों को नाराजगी क्यों होती। जब नेता प्रतिपक्ष का चयन विधायकों की शपथ से पहले ही प्रोटैम स्पीकर के हाथों ही हो जाये तो फिर विपक्ष को कोई नाराजगी कैसे हो सकती है। इन्हीं रिश्तों और व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम है कि पूर्व सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान जारी किया गया आरोप पत्र आज तक विजिलैन्स में नहीं भेजा गया है। इस सरकार का पूर्व सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर था। इस कुप्रबंधन पर लोकाचार निभाते हुये एक श्वेत पत्र भी लाया गया। लेकिन इस श्वेत पत्र पर कोई दाग न पड़ जाये इसलिए किसी कारवाई के कोई आदेश तक नहीं हुये। इससे वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों का सियासी पूर्वाग्रह ही सामने आता है। क्योंकि गंभीर होने पर अपने फिजूल खर्चो पर रोक लगानी पड़ती है। जो मित्रों के दबाव में नहीं लग सकी। इसके अतिरिक्त जो मुद्दे सरकार ने आते ही भाजपा को थमा दिये वह अब उच्च न्यायालय तक पहुंच चुके है। उनमें अदालत से फैसला आना ही हैं। स्मरणीय है कि सरकार ने शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही पिछली सरकार द्वारा अंतिम छः माह के लिये फैसला पलटते हुए छः सौ से अधिक संस्थान बन्द कर दिये थे। इस पर आरोप लगा था की राजनीतिक द्वेष से ऐसा फैसला लिया गया है। क्योंकि इतने अल्प समय में छः सौ मामलों की गुण दोष के आधार पर समीक्षा हो पाना संभव ही नहीं है। यह मामला मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही पूरे प्रदेश में मुद्दा बना दिया गया था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया गया है और लम्बित चल रहा है। आज की बदली परिस्थितियों में कौन सा विधायक यह संस्थान खोले जाने का विरोध कर पायेगा यह सामान्य राजनीतिक समझ का विषय है। इसी के साथ इस सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से एक घंटा पहले छः मुख्य संसदीय सचिवों को शपथ दिलाकर सबको चौंका दिया था। इन नियुक्तियों को तीन अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती मिल चुकी है। इसमें एक याचिका एक दर्जन भाजपा विधायकों द्वारा दायर की गयी है। यह याचिकाएं उच्च न्यायालय में लम्बित चल रही है। इससे पहले भी स्व. वीरभद्र के कार्यकाल में भी ऐसी नियुक्तियां की गयी थी उन्हें उच्च न्यायालय में असंवैधानिक ठहराते हुए तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले को एस.एल.पी. के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। जिस पर असम के मामले के साथ टैग होकर फैसला जुलाई 2017 में आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्य विधायिका को ऐसा कानून बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट फैसले के बावजूद ऐसी नियुक्तियां किये जाने का कोई कारण प्रदेश की जनता के सामने ही नहीं आ पाया है। जनता इससे अवांछित बोझ मान रही है। अब इस मामले में उच्च न्यायालय का फैसला जल्द आने की संभावना बढ़ गई है। स्वभाविक है कि एक दर्जन भाजपा विधायकों की याचिका को भाजपा हाईकमान की सहमति रही ही होगी। इसमें फैसला आने पर यह तो माना ही जा रहा है कि पूर्व की तर्ज पर यह नियुक्तियां भी असंवैधानिक करार दी जायेगी। लेकिन यह संभावना भी नकारी नहीं जा रही है कि इनके आचरण के परिदृश्य में कहीं इन्हें विधायकी से भी हाथ न धोना पड़ जाये। भाजपा इस मामले का पराक्षेप हर हालत में लोकसभा चुनाव से पहले करवाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठायेगी यह तय है। इस फैसले से कांग्रेस संगठन और सरकार के समीकरणों में बदलाव आयेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों बोर्डों में ताजपोशियां तथा क्षेत्रीय असंतुलन जो अनचाहे ही खड़ा हो गया है ऐसे मुद्दे होंगे जो सरकार की सेहत पर असर डालेंगे ही। इस वस्तुस्थिति में लोस चुनाव के उम्मीदवारों का चयन भी आसान नहीं होगा।

राज्यपाल ने लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि करुणा, सहानुभूति और समुदाय की भावना व्यक्तियों और उनके परिवारों को भावनात्मक सहयोग और ऊर्जा प्रदान कर सकती है क्योंकि उन्हें कैंसर के इलाज के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

राज्यपाल गेयटी थिएटर, शिमला में सिमला सैनिटेरियम एंड ऑस्पिटल ऑफ सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट्स द्वारा 'कैंसर-एक बढ़ती चिंता' विषय पर आयोजित सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कैंसर एक चिंताजनक विषय है, जिसने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों के जीवन पर असर डाला है और मौजूदा चुनौती बन गया है, जो न केवल नैदानिक व्यक्तियों बल्कि उनके परिवारों, दोस्तों और समुदायों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कैंसर अपने विभिन्न रूपों में एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है और हमें इस पर ध्यान देने, संसाधनों और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कैंसर में प्रत्येक आंकड़े के पीछे एक व्यक्तिगत कहानी, एक मानवीय चेहरा और इस बीमारी के निरंतर बोझ से प्रभावित एक समुदाय है।

राज्यपाल ने कहा कि हर साल एक करोड़ लोग कैंसर से जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, जो लगभग छह में से एक मौत के लिए जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रगति के अलावा कैंसर का सामना करने वाले लोगों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर बल देते हुए कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की वकालत करें और उनमें निवेश करें जो शुरुआती जांच और हस्तक्षेप को प्राथमिकता देती हैं।

सम्मेलन में यह अवगत करवाया गया कि वर्ष 2020 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी), डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी विश्व कैंसर रिपोर्ट से पता चला कि एशिया में इस घातक बीमारी के वैश्विक मामलों का 49.3 प्रतिशत हिस्सा है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि 2020 से 2040 तक एशिया में कैंसर के नए मामलों में 59.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट, 2020 के अनुसार भारत में कैंसर से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 2.7 मिलियन है और हर साल कैंसर के लगभग 1.39 मिलियन मामले पंजीकृत होते हैं, जिसके 2040 तक बढ़कर 20 लाख होने का अनुमान लगाया गया है।

इससे पहले चिकित्सा निदेशक डॉ. जैकब प्रभाकर चिन्द्रुपु ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट दुनिया में सबसे बड़े प्रोटेस्टेंट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता हैं और 25 से अधिक देशों में 200 से अधिक अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि सेनिटोरियम अस्पताल शिमला के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी और एक सदी से भी अधिक समय से यह हिमाचल प्रदेश के बेस अस्पताल और दूर-दराज के क्षेत्रों में समुदायों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इस अवसर पर कोलंबिया यूनियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स, यूएसए के अध्यक्ष डॉ. डेव वीगली ने राज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर भारत और विदेश से कैंसर विशेषज्ञ, संकाय और विभिन्न विभागों के प्रमुख भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने पुलिस खेलकूद एवं कर्त्तव्य प्रतियोगिता का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पुलिस ग्राउंड, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित 52वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता-2023 का शुभारंभ किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस बल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने, खेलों में भागीदारी के साथ-साथ हर क्षेत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसके लिए पुलिस बलों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस बलों से समाज की अपेक्षानुसार और अधिक संवेदनशील होने का आग्रह किया।

राज्यपाल ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं और डयूटी मीट विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ लाते हैं, इससे एक-दूसरे को जानने और समझने के साथ-साथ टीम वर्क की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल खेल भावना से प्रतिस्पर्धा करते हैं और शांति के संरक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका बखूबी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान पुलिस बलों को अनेक चुनौतियों और मानसिक दवाब का सामना करना पड़ता है इसलिए इस तरह की प्रतियोगिताएं उनके स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस बलों से नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने का आग्रह किया।

इससे पहले, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और कहा कि पुलिस की यह प्रतियोगिता कोविड महामारी के कारण 3 वर्ष के उपरांत आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के लगभग 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

आयोजन सचिव, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) जहूर हैदर जैदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर सांसद किशन कपूर, उप-महापौर सर्व चंद गलोटिया, पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया, उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल, पुलिस अधिकारी, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से शिमला ग्रामीण, ठियोग और नारकण्डा के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उपस्थित थे।

इससे पहले, राजभवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की 17 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यात्रा के पहले चरण में जनजातीय जिलों लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश की लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 3799 स्थानों को लक्षित किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारी योजनाओं का संदेश देने वाली विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन गांव-गांव रवाना होंगी। इसमें स्वच्छता, वित्तीय सेवाएं, विद्युत, एलपीजी कनेक्शन, आवास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के साथ संवाद, उपलब्धियों का जश्न, आन-द-स्पॉट क्विज प्रतियोगिताएं, ड्रोन प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर और मेरा युवा भारत स्वयंसेवक नामांकन सहित सार्वजनिक भागीदारी की गतिविधियां शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का लक्ष्य 25 जनवरी 2024 तक 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3600 शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंचना है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की 17 जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार की दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री हिमकेयर स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा का लाभ सभी 3615 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा तथा इसके लिए जिला स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर नामित किए गए नोडल अधिकारी समर्पण और तत्परता से कार्य करेंगे।

इससे पहले, विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य और विभिन्न पहलुओं के बारे में एक प्रस्तुति भी दी गई। इस अभियान में प्रदेश में 90 वाहनों के माध्यम से 20 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

इस अवसर पर लाभार्थियों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव भी साझा किये।

इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाला लघु नाटक 'धरती कहे पुकार के' भी प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, उपायुक्त आदित्य नेगी, अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

राजभवन में मनाया गया असम स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में असम राज्य के स्थापना दिवस पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

राज्यपाल ने कहा कि असम उत्तर पूर्वी भारत का एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागानों, रेशम उत्पादन और आकर्षक पारंपरिक कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि असम राज्य के लोग अपनी संस्कृति, खान-पान और रीति-रिवाजों से विविधता में एकता की आदर्श मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि असम में कई धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जहां देश और दुनिया भर से लोग आते हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल में रह रहे असम राज्य के लोगों को शाल और टोपी भेंट कर सम्मानित भी किया।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा इस अवसर पर उपस्थित थे।

राजभवन में मनाया गया नागालैंड का स्थापना दिवस

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत की ताकत इसकी विविधता और एकता में निहित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों की कला, संस्कृति और रीति-रिवाजों को जानने और समझने से इनमें परस्पर सहयोग की भावना और बढ़ेगी। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के दृष्टिकोण से भारत की एकता एवं अखण्डता और मजबूत होगी।

वह राजभवन, शिमला में नागालैंड स्थापना दिवस के अवसर पर हिमाचल में रहने वाले नागालैंड के निवासियों से संवाद कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि नागालैंड के निवासी साहसी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्पबद्ध हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओत-प्रोत नागालैंड वासियों ने देश की विविध संस्कृति को और समृद्ध करने में निरंतर योगदान दिया है।

राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत आवंटित होंगे 100 करोड़ रुपये:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी

को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लम्बे समय से लम्बित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि 1 एवं 2 दिसम्बर, 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा तथा लम्बे समय से लम्बित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। उन्होंने कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये।

ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे और हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से सम्बंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए और इस संबंध में संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय एवं सहयोग से दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांगड़ा जिले के ढगवार में प्रस्तावित अत्याधुनिक दूध संयंत्र की प्रगति की भी समीक्षा की और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसका कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्रे के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य प्रशासनिक सचिव शामिल हुए।

विशेष पंजीकरण चिन्ह के लिए ई-आक्शन

शिमला/शैल। निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप ने बताया कि विभाग 04 दिसम्बर, 2023 से विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के आवंटन के लिए ई-ऑक्शन शुरू करने जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला के लिए HP63F-0001 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, मण्डी के लिए HP33G-0001 और (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के लिए HP68C-0001 ई-ऑक्शन होगी।

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 47 के तहत इच्छुक व्यक्ति जो हिमाचल का निवासी हो या जिसके पास राज्य में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, विशेष पंजीकरण चिन्ह 0001 के लिए परिवहन विभाग की वैबसाईट https://himachal.nic.in/transport पर जा कर ई-ऑक्शन फैन्सी नम्बर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।

ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली 5,00,000 रुपये से आरम्भ होगी। आरम्भिक पंजीकरण के दो हजार रुपये होंगे, जिन्हें वापिस नहीं किया जाएगा। न्यूनतम बोली की 30 प्रतिशत राशि 1,50,000 रुपये जमा करवानी होगी। यह सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को असफल रहने पर पांच दिनों के भीतर वापिस कर दी जाएगी। आवेदनों का पंजीकरण सोमवार 4 दिसम्बर, 2023 को प्रातः 10 बजे से शनिवार 9 दिसम्बर, 2023 सांय 5 बजे तक होगा और आवेदक बोली में भी साथ-साथ भाग ले सकते हैं। रविवार को पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा और आवेदक केवल ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बोली की शुरूआत बोली के न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 20 प्रतिशत राशि (1,00,000 रुपये) की बढ़ोतरी के साथ होगी। बोली के लिए प्रारम्भिक राशि 6,00,000 रुपये इसके पश्चात् बोली न्यूनतम मूल्य 5,00,000 रुपये की 10 प्रतिशत राशि जो कि 50,000 रुपये होगी, के साथ ही बढ़ सकती है। ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार सांय 5 बजे घोषित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता को बकाया राशि तीन दिन के भीतर 13 दिसम्बर, 2023 तक जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा। उसके उपरान्त ही नम्बर आवंटित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अगर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जो कि 1,50,000 रुपये बनती है, वापिस नहीं होगी व सरकारी कोष में जमा होगी। यह पंजीकरण नम्बर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाऐगा। इस नम्बर के लिए विभाग द्वारा पुनः बोली लगाई जाएगी।

प्रदेश भर में 13,950 इंतकाल और तकसीम के 527 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ प्रदेश सरकार के विभिन्न निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुरूप प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों के आयोजन से लम्बे अरसे से लम्बित मामलों का समाधान सुनिश्चित हुआ है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 01 और 02 दिसंबर, 2023 को प्रदेश भर में तहसील स्तर तक आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल के लम्बित 13,950 तथा तकसीम के 527 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर, 2023 तक प्रदेश में इंतकाल के 21,212 मामले लम्बित थे, जबकि तकसीम के लम्बित मामलों की संख्या 28,470 थी। 01 व 02 दिसंबर को आयोजित राजस्व लोक अदालतों के बाद अब प्रदेश में इंतकाल के 7262 तथा तकसीम के 27,943 मामले लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि इंतकाल के सबसे ज्यादा 3839 मामलों का निपटारा कांगड़ा जिला में किया गया, मंडी में 2190 और शिमला में 2190 लम्बित मामले निपटाए गए, जबकि हमीरपुर तीसरे स्थान पर रहा जहां इंतकाल के 1023 मामलों का निपटाया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि वर्षो से लम्बित राजस्व मामलों की बड़ी संख्या पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कड़ा संज्ञान लेने के बाद प्रदेश में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है तथा अब तक इंतकाल के लम्बित कुल 45,055 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार, वर्षो से लम्बित राजस्व मामलों का निपटारा कर प्रदेश के आम लोगों की समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इंतकाल और तकसीम के लम्बित मामलों का निपटारा 20 जनवरी, 2024 तक करने के निर्देश दिए है तथा सभी जिलों से प्रतिमाह रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। इसके साथ ही निपटाए गए मामलों की पूरी जानकारी नाम, पते व फोन नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदेश सरकार हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा शीघ्र प्रदान करने को प्रतिबद्ध:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। सिरमौर जिले के हाटी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए कठिन एवं लम्बा संघर्ष किया है और उन्हें यह हक जल्द से जल्द दिलाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। यह बात राजस्व, बागबानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने संवैधानिक (अनुसूचित

जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन और सिरमौर जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसगिरि क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी लेकिन इस अधिसूचना में अस्पष्टता के चलते प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र द्वारा संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है लेकिन जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य वर्ग भी शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। लेकिन केंद्र द्वारा सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकला जा सके।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि हाटी के लोगों को शीघ्र से शीघ्र अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित लाभ मिले। उन्होंने जनजातीय विकास विभाग से कानूनी प्रावधानों के तहत हाटी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान के विकल्प तलाशने को कहा ताकि उन्हें अनुसूचित जनजाति के तहत मिल रही सुविधाएं सुलभ हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गो को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी और उसी के आधार पर आगामी नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से न देखें और यह सुनिश्चित करें कि सभी समुदायों में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले की गंभीरता को समझती है और इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की जायेगी और स्थायी हल निकला जाएगा।

इस अवसर पर रेणुका जी से विधायक विनय कुमार, प्रधान सचिव, जनजातीय विकास, ओंकार चंद शर्मा, सचिव, विधि, शरद कुमार लगवाल, केंद्रीय हाटी समिति (गिरिपार क्षेत्र जिला सिरमौर) के अध्यक्ष अमीचंद कमल, गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति (जिला सिरमौर) के अध्यक्ष अनिल मंगेट, अन्य पिछड़ा वर्ग संगठन (गिरिपार क्षेत्र जिला सिरमौर) के अध्यक्ष धरम पाल, वरिष्ठ अधिकारी व हाटी समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री को अनपी मांगों से अवगत करवाया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डो और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी बजट में इन वर्गो के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल की जाएंगी।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी, विधायक नीरज नैय्यर और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित थे।

दिल और दिमाग के टकराव में, हमेशा दिल की सुनो क्योंकि दिमाग गलत निर्णय ले सकता है, लेकिन दिल कभी नही। ...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्यों हारी कांग्रेस

पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक में चुनावी जीत हासिल करके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में भी मुफ्ती के वायदों के सहारे जो चुनाव जीतने की उम्मीद लगा रखी थी उसे परिणामों ने धराशाही कर दिया है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस से बड़े वायदे परोस दिये और जनता अपना लाभ देखकर भाजपा की ओर होली। 2014 से 2023 तक जितने भी संसद से लेकर विधानसभा तक के चुनाव हुये हैं हर चुनाव मुफ्ती के वायदे पर लड़ा गया है। मुफ्ती के इन वायदों की कितनी कीमत सरकारी खजाने और आम आदमी को उठानी पड़ती है इस पर कभी सार्वजनिक बहस नहीं हुई है। सर्वोच्च अदालत में भी मुफ्ती के मामले पर कोई ठोस कारवाई नहीं हो पायी है। इसलिए जब तक राजनीतिक दल मुफ्ती पर चुनाव लड़ते रहेंगे तब तक चुनावी हार जीत इसी तरह चलती रहेगी। नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को देश 2014 से देखता आ रहा है हर चुनाव में नया वायदा और नया मुद्दा मूल मंत्र रहा है। जिस देश में 140 करोड़ की आबादी में से अभी भी 81 करोड़ को सरकार के मुफ्त अनाज के सहारे जीना पड़ रहा हो उसको कितना विकसित देश माना जाना चाहिये यह सोचने का विषय है। इसलिये चुनावी हार जीत कोई बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाती।

लेकिन इस चुनावी हार के बाद राहुल गांधी के लिये अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठ जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जिस ईमानदारी से देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं के ह्रास का प्रश्न उठाया। जिस तरह से देश के संसाधनों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचे जाने के बुनियादी सवाल उठाये और समाज को नफरती ब्यानों द्वारा बांटे जाने का सवाल उठाया। इन सवालों पर देश को जोड़ने के लिये कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जनता ने उसका स्वागत किया। उससे लगा था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा नुकसान राहुल गांधी की छवि को होगा। क्योंकि इन चुनावों की धूरी कांग्रेस में वही बने हुये थे। इसलिये इस हार से उठते सवाल भी उन्हीं को संबोधित होंगे। इस समय केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारों तक सभी भारी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। राज्य सरकारों पर ही 70 लाख करोड़ का कर्जा है। ऐसे में क्या कोई भी राज्य सरकार बिना कर्ज लिये कोई भी गारन्टी वायदा पूरा कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुये एक वर्ष हो गया है। प्रदेश सरकार हर माह 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है। दस गारंटीयां चुनावों में दी थी जिनमें से किसी एक पर अमल नहीं हुआ है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर इन राज्यों में खूब उछाला। इसी कारण हिमाचल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या मंत्री इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिये नहीं आ पाया। क्या हिमाचल सरकार की इस असफलता का कांग्रेस की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा? जब तक कांग्रेस अपनी राज्य सरकारों के कामकाज पर नजर नहीं रखेगी तब तक सरकारों की विश्वसनीयता नहीं बन पायेगी।

आने वाले लोकसभा चुनावों के लिये जो जनता से वायदे किये जायें उन्हें पूरा करने के लिये आम आदमी पर कर्ज का बोझ नहीं डाला जायेगा जब तक यह विश्वास आम आदमी को नहीं हो जायेगा तब तक कोई भी चुनावी सफलता आसान नहीं होगी। इसलिए अब जब यह देखा खोजा जा रहा है कि कांग्रेस क्यों हारी तो सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से हिमाचल का नाम आ रहा जिसने गारंटीयों से अपनी जीत तो हासिल कर ली परन्तु और जगह हार का बड़ा कारण भी बन गयी।

मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता: अतीत, वर्तमान और भविष्य

एक पिता अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा से बेहतर कुछ नहीं देता – पैगंबर मुहम्मद।

गौतम चौधरी

इस्लाम के प्रनेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मुहम्मद के यह विचार सर्वकालिक और सार्वदेशिक है। एक धर्म के रूप में इस्लाम, मानव व्यक्तित्व के केंद्र में ज्ञान को ही महत्व दिया है। यही कारण है कि इस्लाम के अंतिम संदेशवाहक, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्ञान की महिमा का कई स्थानों पर बखान किया है। अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बावजूद, आज का मुस्लिम समाज शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। ऐसे में स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब चर्चा मुस्लिम महिलाओं की होती है। इस्लामी विद्वान मुहम्मद बाकिर अल सदर ने एक बार कहा था, ''यदि लड़कियों को ठीक से शिक्षित व पोषित किया जाता है और धर्म एवं सांसारिक मामलों के क्षेत्र में उनके अधिकार पूरे किए जाते हैं तो वह एक प्रभावी और लाभकारी समाज की आधारशिला बन जाती है।''

महिलाओं की शिक्षा के लिए पैगंबर और उनके परिवार का रुख दुनिया के सामने एक खुली तस्वीर है। दुनिया की पहली मुसलमान और मुहम्मद साहब की पहली पत्नी खदीजा, एक सफल व्यवसायी ही नहीं थी परोपकारी महिला भी। उन्होंने उस दौर के उत्पीड़ित विधवाओं, परित्यक्त बेटियों और पतियों के द्वारा दुर्व्यवहार करने वाली पत्नियों के लिए काम किया। असाधारण विद्वान और इस्लाम की कार्यकर्ता बीवी फातिमा ने विरासत के अधिकारों के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज उठाई। लेडी आयशा अपने समय के विद्वानों के बीच प्रभावशाली स्थिति के लिए जानी जाती थीं। पैगंबर की नातिन, जैनब बिन्त अली, उस जमाने की एक अविश्वसनीय वक्ता और विद्वान थी, जिसे उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और सीखने के कौशल के कारण 'अकीला आई बान हाशिम' (हाशिम के बच्चों में से एक बुद्धिमान) का खिताब दिया गया था।

9वीं शताब्दी के मध्य में फातिमा अल-फिहरी ने पहले मुस्लिम विश्वविद्यालय के विचार को जन्म दिया। महिलाओं की एक पीढ़ी को आकार देने, कानून, विज्ञान, कला, साहित्य, चिकित्सा, धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करने में इस्लाम कभी भी बाधा नहीं बना। इस्लाम सदा से सामाजिक सक्रियता को बढ़ावा देने में मदद की है। राजनीतिक नेता, विद्वानों और कार्यकर्ताओं के रूप में मुस्लिम महिलाओं के शुरुआती और मध्यकालीन योगदान ने आज के समाज के विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को आईना दिखा है।

मुसलमान धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को संतुलित करने में विफल रहे हैं और खुद को पारंपरिक रूप से निर्धारित ग्रंथों तक सीमित कर लिया है, जबकि इस्लाम प्रगतिशीलता को बढ़ावा देने वाला धर्म रहा है। यह इस्लाम में ज्ञान के फैलाव को विस्तार देने में बाधक बन रहा है। खास कर जिस समाज को गढ़ने और प्रभावशाली बनाने में महिलाओं ने अद्भुद भूमिका निभाई उसी समाज ने महिलाओं पर कई प्रकार की बंदिशें लगा रखी है। यहां तक की शिक्षा से भी उन्हें दूर रखने की कोशिश हो रही है। इस चिंतन ने मुस्लिम महिलाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया। एक प्रचलित घटना के रूप में पुरुष प्रभुत्व धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रेरित आधारों के लिए समाज में महिलाओं की निरक्षर स्थिति पर जोर देता है। धार्मिक पाठ के प्रसारण की व्यापक रूप से गलत व्याख्या की गई है और इसे पुरातनपंथी चिंतन से आबद्ध कर दिया गया है। मदरसा और मकतबों ने लड़कियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को लगातार विकृत परंपराओं के पैटर्न पर संचालित करके प्रतिबंधित कर दिया है। उदाहरण के लिए, महिला शिक्षकों की कमी ग्रामीण समाजों में प्रचलित सामाजिक-आर्थिक गरीबी ने उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए लड़कियों की रुचि को कम कर दिया है और दैनिक वेतन-अर्जन गतिविधियों के लिए उनकी योग्यता को सीमित कर दिया है।

आज मुस्लिम समाज में एक और गलत चलन देखने को मिल रहा है। यहां शादियों में ज्यादा खर्च करने और शिक्षा पर कम खर्च करने के दोहरे मानकों ने लड़कियों के संज्ञानात्मक विकास को पहले ही कुचल कर रख दिया है। एक पति अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए एक महिला डॉक्टर चाहता है लेकिन वह अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता है। अपनी लड़कियों को विज्ञान के बारे में जानने और समझने से रोकता है।

एक बेहतर कल के लिए, मुसलमानों को अपने अस्तित्व में स्वायत्तता और विश्वास को लागू करके अपनी महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सच्चे कदम के रूप में उनकी शिक्षा के लिए आश्वासन और जागरूकता प्राप्त करने में सहायता की जानी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को उनके विकास के लिए अप्रतिबंधित और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकारी पहलों से परिचित होना भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम महिलाओं को उनके शिक्षा के अधिकार को समझने के लिए उचित निर्देश के साथ कुशल तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वैश्वीकरण के इस युग में मुसलमा तभी अपने आप को मजबूत बना पाएंगे जब वे अपने घर की महिलाओं, बहु-बेटियों को आधुनिक शिक्षा से परिचय कराएंगे। भारत में सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कई मुस्लिम महिलाएं अपना जीवन खुशहाल बना रखी है। यही नहीं अपने परिवार को भी वह सही दिशा दे रही है। ऐसे में मुसलमानों को महिलाओं के लिए थोड़ा जगह तो देना ही होगा अन्यथा भारत के मुसलमान अन्य समाज की तुलना में पिछड़ते चले जाएंगे।

नगर निगम के महापौर और उपमहापौर के चुनाव में विधायकों को मतदान का अधिकार देने का क्या औचित्य?

शिमला। कई बार क्षणिक लाभ के लिये हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं और इसके कारण या तो बाद में निर्णय बदलना पड़ता है या ऐसे निर्णय के दुष्प्रभाव का सारी व्यवस्था पर असर पड़ता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें लगता है कि शायद उसके दूरगामी प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है।

इस निर्णय के अनुसार नगर निगमों के महापौर और उपमहापौर के चुनाव में स्थानीय विधायकों को भाग लेने और मतदान करने का अधिकार दिया गया है, शायद यह निर्णय कानून की कसौटी पर सही नहीं उतरेगा।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप यदि महापौर और उपमहापौर के चुनाव में विधायकों को मतदान का अधिकार होगा तो फिर क्या जब नगर परिषदों, नगर पंचायतों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो उस में भी विधायकों को मतदान का अधिकार होगा? क्या विधान सभा का चुनाव जीत कर विधायक को विधानसभा के अतिरिक्त स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान का अधिकार मिल जायेगा?

इसी के आधार पर सांसदों को यह अधिकार होगा कि उनके चुनाव क्षेत्र में आने वाले सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में सांसद भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। फिर मामला केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के मुखिया चुनने तक ही सीमित नहीं होगा। फिर सांसद को अपने राज्य में मुख्यमन्त्री के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मांगने से कैसे रोका जा सकेगा और यह प्रश्न केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

इसीलिये मैंने कहा कि क्षणिक लाभ के लिये दूरगामी परिणामों वाले निर्णय लेने में पूरा विचार विमर्श होना चाहिए। एक दो नगर निगमों के महापौर और उपमहापौर के चुनाव के लालच के साथ साथ प्रदेशव्यापी और राष्ट्रव्यापी परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे निर्णय तर्कसंगत नहीं होते, संविधान निर्माताओं ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये नेता अर्थात प्रधानमन्त्री (सरकार का मुखिया) का चुनाव करने का अधिकार केन्द्र में केवल लोक सभा के सांसदों को दिया है, राज्य सभा के सांसदों को यह अधिकार नहीं है। इसी प्रकार प्रदेश सरकार का मुखिया, मुख्यमन्त्री विधान सभा के विधायक चुनते हैं विधान परिषद सदस्यों को यह अधिकार नहीं है।

इसलिये नये आदेशानुसार चुने गये महापौर और उपमहापौर का चयन क्या कानून की कसौटी पर न्यायालय में टिक पायेगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा।

सुंदरनगर की सुनीता देवी ने लिखी कामयाबी की इबारत

शिमला। कवि सोहन लाल द्विवेदी की लिखी कविता कि यह पंक्तियां ''लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती'' मंडी जिला के सुंदरनगर के भरज्वाणु की सुनीता देवी पर पूरी तरह से फिट बैठती हैं। पति के अकसर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर अपने घर की छत पर पनीरी उगाने का कार्य शुरू करने वाली सुनीता देवी एक साल में तीन से साढे तीन लाख रुपये की कमाई कर रही है। सुनीता देवी पनीरी उगाने के पर पनीरी उगा कर आय का सहारा बनाने के बारे में सोचा। जिससे कि वह घर पर रहकर अपने बीमार पति का भी ख्याल रख पाएगी। इसके साथ ही पनीरी को उगाने के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने घर की छत पर लकड़ी के बाक्स बनाकर उसमें विभिन्न सब्जियों की नर्सरी तैयार की और बाजार में बेचना शुरू किया। इससे सुनीता देवी को एक लाख तक की कमाई होने लगी। सुनीता देवी छत पर गोभी, बंद

गोभी, ब्रोकली, घीया, करेला, खीरा, प्याज आदि के पनीरी उगाती है और बाजार में बेचती है। गांव के लोग उनसे घर पर आकर ही पनीरी ले जाते हैं और इस तरीके को भी सीखते हैं। सुनीता देवी ने पनीरी को उगाने के कार्य में सफलता मिलने पर सरकार की सहायता से प्राकृतिक खेती करने की सोची। इसके लिए उन्होंने जमीन लीज पर लेकर खेती शुरू कर दी। सुनीता देवी का कहना है कि पनीरी बेचकर और प्राकृतिक खेती करके वह तीन से साढ़े तीन लाख रुपये सालाना की आय अर्जित कर रही है।

सुनीता देवी ने प्रदेश सरकार और कृषि विभाग का धन्यवाद करते हुए बताया उनकी सफलता के पीछे प्रदेश सरकार विशेषकर कृषि विभाग का योगदान रहा है। उन्हें समय – समय कृषि विकास से कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी के साथ आर्थिक सहायता मिलती रही है।

उधर, उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि सुनीता देवी जैसी मेहनती महिलाओं को कृषि, उद्यान सहित अन्य विभागों की स्वावलंबी योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर महिलाओं की आय बढ़ाने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

सुनीता देवी का कहना है कि पति के अकसर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर घर की छत साथ लीज पर ली गई भूमि पर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियों का भी उत्पादन कर रही है।

सुनीता देवी केवल पांचवी पास है और आज वह छत पर पनीरी उगाने का कार्य करने पर देशभर में नाम कमा रही है। उन्हें नाचन जनकल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति ने उनके घर आकर सम्मानित कर चुके हैं वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी महिला किसान दिवस के अवसर पर सुनीता के साथ वर्चुअली बातचीत कर उनके सराहनीय कार्य के लिए तारीफ की है।

कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कृषि शिक्षण संस्थानों के बच्चे सुनीता देवी के पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। अब तक वह 300 से अधिक बच्चों को प्राकृतिक खेती और छत पर पनीरी के बारे में प्रशिक्षण दे चुकी हैं।

छत पर पनीरी उगाने के कार्य को लेकर सुनीता देवी इलाके के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन कर उभरी है। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि मजबूत इच्छाशक्ति से हजारों मुश्किलों से पार पाया जा सकता है और कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती हैं।

कृषि क्षेत्र की योजनाओं से किसानों के जीवन में आ रही खुशहाली

सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दो योजनाओं में 18 करोड़ रुपये का प्रावधान

शिमला। किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश में कृषि क्षेत्र निरन्तर विकसित हो रहा है। प्रभावी कृषि योजनाओं के माध्यम से किसानों और कृषि उद्यमियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वहीं, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाने की सरकार की कवायद सफलता की नई इबारत लिख रही है।

प्रदेश सरकार की जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत राज्य में उपयुक्त स्थानों पर चेक डैम व तालाबों का निर्माण किया जाता है। इनमें एकत्रित जल का उपयोग कर किसान व्यक्तिगत लघु उठाऊ सिंचाई तथा बहाव सिंचाई योजनाओं को बनाकर खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। योजना के अंतर्गत सामुदायिक लघु जल संचयन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शत – प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2022 – 23 में 25 करोड़ रुपये व्यय कर प्रदेश के 80.26 हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाओं का सृजन कर 345 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023 – 24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 5.18 करोड़ रुपये व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया गया है।

प्राकृतिक जल स्रोतों के नवीकरण और सामुदायिक क्षेत्रों में कुहलों को सुदृढ़ कर सिंचाई कार्य में इनका उपयोग करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सरकार की प्रवाह सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुहलों के स्रोतों का नवीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कुहलों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवेल तथा उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 – 23 में 600 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल कर 820 किसानों को लाभान्वित किया गया तथा वर्ष 2023 – 24 में 8 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया जिसमें से अब तक 4.56 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रयोगशाला से निकालकर खेत तक पहुंचाने की अवधारणा को साकार कर रही है। पहाड़ों में कृषि कार्यों सम्बंधी कठिनाइयों के दृष्टिगत किसानों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के लिए राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चारा कटर, मक्का शैलर, गेहूं थ्रेशर, स्प्रेयर, ब्रश कटर, एस.एस. हल, एम.बी. हल इत्यादि उपकरण 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023 – 24 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कृषक कल्याण को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कई प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ – साथ महत्त्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनसे प्रदेश के किसानों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं और ऊपज में बढ़ौतरी से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है।

पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने की स्वीकृति

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत राज्य का प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक 4000 रुपये प्रतिमाह जेब खर्च प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को 2 लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने बाद विवाह किया। यह राशि एक बार ही देय होगी।

बैठक में पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद और जिला मंडी के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल (एसएलबीएसजीएमसीए) के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की। इससे उदार प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियन्ता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

संयुक्त पटवार एवं कानूनगो महासंघ की बैठक मे 25 सूत्रीय मांगपत्र पर चर्चा

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवार/कानूनगो महासंघ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें महासंघ के 25 सूत्रीय मांगपत्र पर विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग लोगों से सीधे जुड़ा देश के सबसे पुराने विभागों में से एक है। राजस्व सम्बंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कार्यों में पटवारी एवं कानूनगो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से निपटने में इस संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी समस्याओं से भली-भांति परिचित है और इनके उचित समाधान के लिए ठोस एवं सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा पटवारी व कानूनगो से सम्बंधित मांगों पर चर्चा के लिए निदेशक, भू-अभिलेख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति समय-समय पर हिमाचल प्रदेश पटवारी एवं कानूनगो संघ के साथ बैठक का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के सहयोग से एचआरएमएस साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे सालाना एसीआर समय पर उपलब्ध होने के साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पटवारियों के पद भरने को हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। पटवारी/कानूनगो को उचित स्टेशनरी व्यय, बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने, सुधार समितियों में महासंघ को शामिल करने, कानूनगो की संयुक्त वरिष्ठता सूची उपलब्ध करवाने सहित अन्य सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर पटवारी एवं कानूनगो की भूमिका का बहुत महत्व है। वे पूर्ण जिम्मेवारी एवं अधिक पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने तथा पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ सुनिश्चित करने में भी इस वर्ग की भूमिका अहम है।

बैठक में प्रधान सचिव, राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने विभिन्न मांगों पर विभागीय पक्ष रखा।

महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आपदा के दौरान प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया और महासंघ भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ा रहा।

संयुक्त सचिव, अनिरूद्ध चौहान ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

बैठक में राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, महासंघ के प्रदेश तथा जिला स्तर के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के समारोह में आयेंगे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 11 दिसंबर को राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिला कांगड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगे। यह बात मुख्यमंत्री ने हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा की नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त करने ओक ओवर पहुंचे समर्थकों को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यशवंत छाजटा ने अपने जीवन के 25 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, जिसके कारण उन्हें सरकार में नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पद दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने धर्मशाला नगर निगम के चुनाव में महापौर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर रणनीति बनाकर मैदान में उत्तरेगी और भाजपा को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी व सरकार व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर हिमुडा उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने मुख्यमंत्री का उनकी नियुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया।

कड़ू व चिरायता की खेती में जाइका को मिली पहली कामयाबी

शिमला/शैल। प्रदेश में विलुप्त होते औषधीय पौधे कडू और चिरायता की खेती कर जाइका वानिकी परियोजना ने पहली कामयाबी हासिल की। जिला मंडी के नाचन वन मंडल के तहत छैन मैगल, बुखरास और रोहाल गांव से संबंध रखने वाली महिलाओं के एक समूह ने उक्त दो औषधीय प्रजातियों की पहली खेप उतार दी। नाचन वन मंडल के धंगयारा में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के समक्ष कडू और चिरायता की खेप को दर्शाया गया। इस अवसर पर नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि विलुप्त हो रहे ऐसी प्रजातियों की खेती कर मिसाल कायम की है। नागेश कुमार गलेरिया ने कहा कि कडू और चिरायता की खेती करने के बाद अब महिला समूह को पैसे मिलना भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट में इन औषधीय गुणों वाले कडू और चिरायता की मांग दिन-प्रति दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में जाइका वानिकी परियोजना इस पर और अधिक काम करेगी। कार्यशाला में जैव विविधता विशेषज्ञ डा. सुशील काप्टा, डीएफओ नाचन एसएस कश्यप, वीपी पठानिया, जड़ी-बूटी सैल से जड़ी-बूटी सैल से नेहा चक्रवर्ती, हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डा. लाल सिंह समेत 150 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने यहां उपस्थित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका कमाने के गुर सिखाए।

हिमाचल ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 में जीते दो प्रतिष्ठित पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लेह में आयोजित डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव और अवार्ड्स- 2023 के 12वें संस्करण में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। यह कार्यक्रम गोव कनेक्ट एंड इलेंग मीडिया द्वारा लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान के लिए आयोजित किया गया।

सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशासन) और मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने राज्य की ओर से दोनों पुरस्कार प्राप्त किए। प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण एवं बेहतरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किए गए।

डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग के तहत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 और हिम परिवार परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए।

डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये पुरस्कार डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जन कल्याण में प्रदेश में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 राज्य में एक केन्द्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण मंच है। इसके माध्यम से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को सुव्यवस्थित किया गया है। टोल फ्री नंबर, वेब एप्लिकेशन और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज शिकायतों के निवारण के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल और सुलभ प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से अब तक 90 विभागों के 10,000 अधिकारियों द्वारा 6,04,557 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 5,93,693 (98 प्रतिशत) शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, नागरिकों की संतुष्टि के साथ 4,25,067 (70 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा किया गया है। यह देश भर में चलाई जा रही ऐसी केन्द्रीय शिकायत निवारण हेल्पलाइनों में से सबसे अधिक है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के लोगों के लिए लिए एक केन्द्रीय कॉल सेंटर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को 181 महिला हेल्पलाइन, एचआरटीसी हेल्पलाइन, 1077-आपदा प्रतिक्रिया, जीएसटी हेल्पलाइन, नशामुक्ति के लिए परामर्श आदि के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी आरम्भ किया जा रहा है।

हिम परिवार परियोजना एक पात्रता-आधारित प्रबंधन प्रणाली है, जिसे एक एकीकृत राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के व्यापक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य के दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। यह पहल पात्र नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक डेटा का उपयोग करने, उन्हें सूचित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने में सहायक है। यह परियोजना भविष्य के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए भी डेटा उपलब्ध करवाएगी।

लक्ष्यों को पार करते हुए...

एसजेवीएन सुदृढ़ता से विकास और विस्तार की ओर अग्रसर

2026 तक 12000 मेगावाट के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए...

भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल और ऊर्जा समृद्ध भारत बनाने का एक विज़न दिया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा उपक्रम के रूप में, एसजेवीएन बड़े पैमाने पर अपनी क्षमतागत वृद्धि और एक विविध पोर्टफोलियो के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर है।

जल विद्युत | ताप विद्युत | पवन ऊर्जा | सौर ऊर्जा
विद्युत ट्रांसमिशन एवं ट्रेडिंग | परियोजना परामर्श

एसजेवीएन लिमिटेड

(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
एक 'मिनी रत्न' एवं शेड्यूल 'ए' पीएसयू

पंजीकृत कार्यालय : शक्ति सदन, कारपोरेट मुख्यालय, शनान, शिमला–171006, हिमाचल प्रदेश (भारत)
समन्वय कार्यालय : ऑफिस ब्लाक, टॉवर–1, 6वीं मंजिल, एनबीसीसी कॉम्पलैक्स, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 (भारत)

वेबसाईट : www.sjvn.nic.in SJVNLtd @SjvnLimited sjvn-limited

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 - 2805015, 94180 - 15015 फैक्स: 2805015

सरकार और संगठन का यह टकराव सरकार की सेहत के लिए घातक होगा

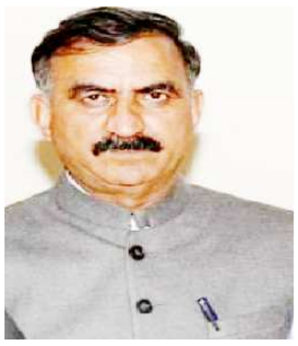

सरकार और संगठन का यह टकराव सरकार की सेहत के लिए घातक होगा

शिमला/शैल। साल पूरा होने जा रहा है इस अवसर पर सरकार धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसके लिये मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित भी कर आये हैं क्योंकि एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। लेकिन सरकार के इस आयोजन की कोई औपचारिक जानकारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह को नहीं दी गयी है। प्रतिभा सिंह ने सरकार द्वारा कोई जानकारी न दिये जाने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकारी है। कांग्रेस संगठन की अपनी ही सरकार द्वारा इस तरह की नजर अन्दाजी प्रदेश के राजनीतिक हल्कों में गंभीर चर्चा का विषय बनी हुयी है। क्योंकि अभी-अभी तो कांग्रेस को तीन राज्यों में हार का झटका लगा है। ऐसे में प्रदेश सरकार और संगठन के इस टकराव को विश्लेषक अलग नजर से देख रहे हैं। सरकार संगठन की अनदेखी करती आ रही है इस आश्य की शिकायतें हाईकमान तक पहुंचती रही हैं। सरकार की कार्यशैली से क्षेत्रीय असंतुलन उस सीमा तक पहुंच गया है जहां उसे अब संतुलित कर पर पाना मुख्यमंत्री के लिये भी असंभव होता जा रहा है। क्योंकि यह असंतुलन मित्रों को स्थापित करने के कदमों का प्रतिफल है। जो सरकार कर्ज के आंकड़ों के दस्तावेजी प्रमाणों को भी झुठलाने का साहस करें उससे उसकी बजटीय समझ पर भी सवाल उठते हैं। आज एक वर्ष के अवसर पर यदि सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की जाये तो सबसे बड़ी उपलब्धि लेने की ही आती है। जो गारंटीयां चुनावों में जनता को परोसी थी उनकी पूर्णता की ओर चरणवद्ध तरीके से पूरा करने के आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ भी सरकार के पास कहने और देने को नहीं है। इस परिदृश्य में आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद पार्टी को चारों सीटों के लिये प्रत्याशी तय करना भी आसान नहीं होगा। राजनीतिक पंडित जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने में स्व. वीरभद्र की विरासत का विशेष योगदान रहा है। इस विरासत की अनदेखी चुनावी राजनीति में महंगी पड़ेगी। क्योंकि सरकार का अपना कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। अभी सरकार के सिर पर मुख्य संसदीय सचिवों के मामले की तलवार लटकी हुई है। यदि कहीं इन लोगों को अदालत ने विधायकी से भी आयोग्य घोषित कर दिया तो सरकार का बना रह पाना कठिन हो जायेगा। हालात नये चुनावों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता होगी कि वह इस सरकार को अपने ही भार से गिरने के कगार पर लाकर खड़ा कर दे। जब कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर हो रही हो तो ऐसे समय में एक मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही प्रदेश अध्यक्ष और संगठन की अनदेखी के प्रयासों को विश्लेषक राजनेताओं की नीयत से जोड़कर देखने को विवश हो जायेंगे। क्योंकि इस तरह के प्रयास किसी भी गणित से पार्टी हित नहीं माने जा सकते। यदि सरकार और संगठन का यह टकराव सरकार की बलि लेने के कगार पर पहुंच जाता है तो इसकी सीधी जिम्मेदार कांग्रेस हाईकमान की होगी।

छत्तीसगढ़ के घोटाले का पैसा हिमाचल के चुनाव में लगा:जयराम

क्या जयराम के इस आरोप का कोई जवाब प्रदेश सरकार दे पायेगी? जयराम ने एक ही तीर से तीन निशाने साध दिये।

शिमला/शैल। तीनों हिंदी भाषा राज्यों में कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत ने सारे राजनीतिक समीकरणों को पलट कर रख दिया है। इसका हिमाचल में इस कदर प्रभाव पड़ा है की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम ने सरकार पर ऐसा हमला बोला है जिसके परिणाम दुरगामी और बहुत व्यापक होंगे। जयराम ठाकुर ने यह बड़ा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों जितने घोटाले सामने आये जिनमें कोयला, शराब, गोबर और महादेव ऐप विशेष चर्चित रहे इन घोटालों का पैसा हिमाचल के चुनावों में चुनावी फण्ड के रूप में इस्तेमाल हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किये जाने के सुक्खू सरकार के दावों और प्रयासों पर हमला बोलते हुये सवाल किया कि क्या यह सरकार इन घोटालों पर अमल करने जा रही है। उन्होंने सरकार से छत्तीसगढ़ मॉडल का खुलासा प्रदेश की जनता के सामने रखने की मांग की है।

राजस्थान की बात करते हुये जयराम ने खुलासा किया कि वहां एक लाल डायरी का जिक्र है जिसमें वहां की सरकार के एक मंत्री ने सरकार के सभी घोटालों को अपनी एक डायरी में लिख रखा था। यह बात बाहर आते ही उस मंत्री को सरकार से निकाल दिया गया। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में 19 पेपर लीक के मामले होने का जयराम ने जिक्र उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी खुलासा किया कि सुक्खू सरकार द्वारा दस गारंटीयों को लेकर बोले जा रहे झूठ को भी उन्होंने तीन राज्यों में बेनकाब किया और उसका परिणाम इन नतीजों के रूप में सामने आया है। जयराम ने सरकार द्वारा एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में मनाये जा रहे जश्न के औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठाये हैं।

जयराम द्वारा लगाये गये आरोप भले ही सीधे तौर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है। लेकिन इन आरोपों का जवाब देना सुक्खू सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। अब कांग्रेस के पास हिंदी भाषा राज्यों में केवल हिमाचल ही रह जाता है। इसलिए ऐसे उठने वाले सवालों का जवाब देने की बड़ी जिम्मेदारी यहां के नेतृत्व पर आ जाती है। क्योंकि हिमाचल से केंद्र में एक महत्वपूर्ण मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं। यही नहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी हिमाचल से ही ताल्लुक रखते हैं। परन्तु पिछले एक वर्ष के कार्यकाल पर नजर डालें तो ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं आता है कि हिमाचल सरकार या संगठन के किसी बड़े नाम ने केंद्र पर कभी कोई सवाल उठाया हो। बल्कि ऐसा लगता रहा है कि केंद्र सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उठाये जा रहे सवालों से प्रदेश सरकार का कोई वास्ता ही न हो।

ऐसे में आज जो आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाये हैं वह छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ ही कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी आ जाते हैं। इन सवालों पर प्रदेश सरकार का आचरण कैसा रहता है यह देखना रोचक होगा।